

You have given figures regarding the loss of production due to bad functioning of the coke-oven batteries at Durgapur. You have given certain figures which are as under :

Year	(in tonnes)	
	DSP	ASP
1980-81	141307	2916
1981-82	36090	2793
1982-83	102682	1835

I want to know what is the loss in terms of money.

You have said that moderanisation of the Durgapur Steel Plant will be taken up. We have also said that Durgapur Steel Plant is not for West Bengal only. In the national interest I want to know when are you going to take up modernisation and expansion of Durgapur Steel Plant? Are you conspiring to stall the renovation of Durgapur Steel Plant or do you want to destroy this plant?

SHRI N.K.P. SALVE : As to the allegation of conspiracy I do not know with whom does he mean? I have already stated as to when we are taking it up.

I entirely agree with the Hon. Member to the extent he has said with regard to the functioning of the coke-oven batteries—its working upto the rated capacity is a *sine qua non*—condition precedent to the optimising productivity. We have not been able to do so. Therefore, I have stated in my answer, we are already taking up measures for changing equipment and components of coke-oven batteries not only of Durgapur but in other intergrated plants as well. We are working to improve the quality of coal which is extremely improtant.

He has mentioned that certain figures are incorrect. I shall be grateful to the Hon. Member to let me know

which figures he has found to be incorrect.

As regards conversion of figures—loss in terms money, I will intimate to him the value of this.

#### Foreigners Tribunals in Assam

+

\*207. SHRI ATAL VIHARI  
VAJPAYEE :

SHRI SURAJ BHAN :

Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to lay a statement showing :

(a) since when the Foreigners Tribunals, set up under the Foreigners Tribunal Order 1964 are in existence in Assam;

(b) from time to time what have been their maximum and minimum numbers in the States and reasons therefor;

(c) how many foreigners were identified by them in these 19 years and what happened to those foreigners; and

(d) work done by these Tribunals during President's rule in Assam?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI NIHAR RANJAN LASKAR) : (a) and (b) The Foreigners' Tribunal set up under the Foreigners (Tribunal) Order, 1964 had been in existence in Assam since October, 1964. Four Foreigners Tribunals were set up in Assam by the State Government of Assam in October, 1964. One more tribunal was set up in April, 1965. In October, 1979, in view of the allegations of large-scale influx from Bangladesh, Government of Assam constitute 10 Foreigners Tribunals covering 10 districts of Assam. Thereafter, State Government decided to constitute 6 additional Tribunals at Gauhati, Silchar,

Nowgong, Nalbari, Mangaldoi and Goalpara. 13 Foreigners Tribunals were in existence in the State of Assam prior to promulgation of Illegal Migrants (Determination by Tribunals) Ordinance, 1983. State Government of Assam have issued a notification establishing 20 Tribunals under the provisions of the above Ordinance.

(c) and (d) The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, इससे पहले कि मैं अपना पूरक प्रश्न मंत्री महोदय से पूछूँ, जो उत्तर दिया गया है उसके अंतिम भाग की ओर मैं आपका ध्यान खींचना चाहता हूँ। मैंने जानना चाहा था—

“(c) how many foreigners were identified by them in these 19 years and what happened to those foreigners ; and

(d) work done by these Tribunals during President's rule in Assam.”

इसका जवाब दिया गया है कि जानकारी एकत्र की जा रही है। इस सरकार को जानकारी एकत्र करने के लिए कितने दिन चाहिए ? यह कोई हाल में हुई घटना नहीं है। ट्रिब्यूनल 1964 से काम कर रहे हैं। जो जानकारी सरकार को उपलब्ध है वह सदन के सामने लानी चाहिए था। अध्यक्ष महोदय, इसी तरह के जवाबों से

आसाम में संदेह पैदा होता है कि सरकार विदेशियों के मामले में गंभीरता से विचार नहीं कर रहा है। आप जरा इनको फटकार लगाइए।

अध्यक्ष महोदय, अभी जो अध्यादेश जारी किया गया है वह एक सही दिशा का कदम है। उसके अंतर्गत अभी तक केवल 20 ट्रिब्यूनल कायम किए गए हैं जब कि त्रिपक्षीय वार्ता में सरकार इस सुझाव पर सहमत थी कि हर कांस्टीट्यूँसी में एक ट्रिब्यूनल बनाया जाएगा जिससे विदेशियों को पहचानने का काम जल्दी से हो सकेगा और मतदाता सूचियों में सुधार किया जाएगा और बाकी के चुनावों को भी संपन्न किया जाएगा। मैं जानना चाहता हूँ कि 126 की जगह केवल 20 ट्रिब्यूनल क्यों काम कर रहे हैं। क्या कोई व्यावहारिक कठिनाई है। क्या देश के अन्य भागों के जज आसाम में जाकर काम करने से डरते हैं या सरकार ज्यादा ट्रिब्यूनल बनाकर मामले को हल करना नहीं चाहती, मामले को लटकाए रखना चाहती है ?

गृह मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : अध्यक्ष महोदय, जहाँ तक इल्लिगल माइग्रेंट्स के डिटेक्शन और डिपोटेशन का सवाल है, ये आंकड़े मेरे पास हैं और पहले भी सदन में दिए थे। लेकिन ये विभिन्न ट्रिब्यूनल और अथारिटीज के द्वारा किए गए हैं। जानकारी इस प्रकार है—

वर्ष	डिटेक्शन	डिपोटेशन
1952 से 1960	21723	17107
1961 से 1970	239107	191898
1971 से 1980	113876	109715
1981	1165	1056
1982	4269	- 1529

इस प्रकार से कुल व्यक्ति जिनका डिटेक्शन हुआ है उनकी संख्या 380693 है और डिपोट किए गये हैं 321543, जहाँ तक ट्रिब्यूनल्स का ताल्लुक है, अध्यक्ष महोदय, आसाम गवर्नमेंट ने पहले कहा है कि हम शुरुआत करते हैं 20 ट्रिब्यूनल्स से, लेकिन उनका और मेरा भी संसद में जो आश्वासन है कि प्रत्येक कास्टीट्यूट में एक ट्रिब्यूनल होगा, उस पर आसाम सरकार अभी भी कायम है और ऐसा नहीं है कि जजेज वहाँ नहीं जाना चाहते। उनको जो अलाउमेंस और फेमिलिटीज दी जा रही है उनकी वजह से 31 लोगों ने कई प्रांतों से वहाँ जाने के लिए आप्ट किया है। उनके नाम आसाम सरकार के पास भेज दिए गए हैं। 8 नाम सीधे आसाम सरकार के पास आए हैं। जैसे-जैसे नाम आते जाएंगे और ट्रिब्यूनल्स इस प्रकार के बनाते जाएंगे और ये ट्रिब्यूनल्स अपना काम प्रारंभ करेंगे। जहाँ तक विदेशियों को निकालने का ताल्लुक है 25 मार्च, 1971 के बाद जो आए हैं उनको निकालने के बारे में सरकार त्वरित कार्यवाही करना चाहती है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : इससे पहले कि मैं दूसरा पूरक प्रश्न पूछू, मंत्री महोदय ने जो जवाब दिया है, उसका स्पष्टीकरण पूछना चाहता हूँ। मंत्री महोदय ने जवाब दिया, उन आंकड़ों के बारे में जानना चाहता हूँ। जो पहचाने गए और जो निकाले गए, उनकी संख्या दी है। दोनों में अन्तर है। जो पहचान लिए गए और निकाले नहीं गए, वे कहाँ गए ?

अभी जो अध्यादेश जारी किया गया है, गृह मंत्री महोदय ने उल्लेख किया है कि 1971 के बाद जो आए हैं, उनकी पहचान

ट्रिब्यूनल करेगा। क्या यह संभव नहीं है कि 1971 के बाद जो आए हैं, वे भी यह दावा करें कि 1971 से पहले आए थे ? क्या ट्रिब्यूनल को सारे मामले में 1971 से पहले के वर्षों का ध्यान रखकर जाना नहीं पड़ेगा ? दूसरी बात यह है कि विदेशियों को पहचानना किसका काम है। यह सरकार की जिम्मेदारी है या नागरिकों की। अभी जो अध्यादेश जारी किया गया है उसमें जिम्मेदारी नागरिकों पर डाल दी गई है। ट्रिब्यूनल तब देखेगा जब उसको शिकायत मिलेगी और यह भी शतं लगा दी गई है कि शिकायत करने वाला तीन किलोमीटर के भीतर रहने वाला होना चाहिए। आसाम में कई इलाके ऐसे हैं जहाँ मीलों तक बंगलादेश के आए हुए लोग बसे हैं। दुश्मनी मोल लेकर कौन शिकायत करने जायेगा ? मैं जानना चाहता हूँ कि क्या इस पहलू पर भी विचार किया है ?

श्री प्रकाश चन्द्र सेठी : यह माननीय सदस्य का पूरक प्रश्न या पहले सवाल के जवाब में या दूसरा प्रश्न भी आ गया। जो बाकी के बचे करीब 60 हजार व्यक्ति हैं, उनके मामले कई वेरियस कोर्ट्स में पेडिंग हैं। इस वजह से इनके बारे में कार्यवाही नहीं हुई है। इसका मतलब यह नहीं है कि उनके बारे में सरकार को कोई बिना नहीं है।

जहाँ तक अध्यादेश का सवाल है उसमें तीन मील का दायरा इसलिए रखा गया है कि अनावश्यक तौर पर हेरासमेंट नहीं हो और कोई भी व्यक्ति किसी की भी शिकायत करके उसको फारेनर घोषित करने की कोशिश करे, यह नहीं हो। जहाँ तक 1971 से पहले आने वाले लोगों का सवाल है, बाद में आने वाले लोग भी यह

क्लेम कर सकते हैं कि हम पहले आए हैं। इसके बारे में ट्रिब्युनल्स का पूरा अधिकार दिया गया है कि वे इसकी छानबीन करें। उसके प्रॉपर इन्फुमेंट्स और सारी गवाही लेने के पश्चात् फैसला करें। ट्रिब्युनल्स फैसला करेंगे, उसके अपीलेट ट्रिब्युनल्स भी बनाए गए हैं जिसमें हाई-कोर्ट के स्तर के जज काम करें।

श्री सूरज भाग : अध्यक्ष महोदय, सप्लीमेंटरी पूछने से पहले मैं आपके नोटिस में एक चीज लाना चाहता हूँ। ये सबाल इसलिए दस बजे रख दिए जाने हैं कि हम पढ़ लें। आज सुबह मैं दस बजे आया लेकिन साढ़े दस बजे तक नोटिस आफिस में जहाँ क्वेश्चन-आन्सर की बुकम रखी थी, उसमें यह आन्सर नहीं था। मैंने उनको कहा कि क्या यह क्वेश्चन पोस्टपोन हो गया ? सबने देखभाल करके पीने ग्यारह बजे बड़ी मुश्किल से दिया बल्कि वाजपेयी जी तो बापिस आ गए। इनको क्याल हुआ कि जायद पोस्टपोन हो गया। मुझे जो जबाब मिला उसका पढ़कर उन्होंने अभी सबाल बनाए हैं।

अध्यक्ष महोदय : मैं पता करता हूँ। आइ विल टेक एक्शन।

श्री सूरज भाग : विदेशी मुसपैठियों के कारण आसाम भयानक दौर से गुजर रहा है। इसकी जानकारी हम सबको है। अब यह विदेशी हमारे आसाम तक ही नहीं बल्कि बंगाल, बिहार, त्रिपुरा आदि और भी देश के अन्य प्रदेशों में आ रहे हैं। मैं सरकार से यह जानकारी चाहता हूँ कि क्या उन प्रदेशों में भी इसी किस्म के ट्रिब्युनल्स आप कायम करेंगे ताकि इस बीमारी से छुटकारा पा सकें या और कोई तरीका हो तो बना दीजिए ?

श्री प्रकाश चन्द्र सेठी : अध्यक्ष महोदय, जो बिल पार्लियामेंट के सामने इन्ट्रोड्यूस किया गया है उसमें भारत सरकार ने दूसरे राज्यों में भी ट्रिब्युनल्स बनाने का अधिकार लिया है। जहाँ-जहाँ इसकी आवश्यकता महसूस होगी, वहाँ-वहाँ ट्रिब्युनल्स कायम किए जायेंगे। जहाँ तक डिटेक्ट करने का सवाल है, यह वास्तव में सही है—कि यह जिम्मेदारी सरकार का है। मगर, कोई प्राइवेट सिटीजन भी इसकी शिकायत करना चाहे तो उसको भी यह मौका दिया गया है कि वह इस संबंध में कंप्लेंट कर सकता है।

श्री घटम विहारी बाजपेयी : तीन मिनट की जतन नहीं होनी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : सरकार की जिम्मेदारी है। उसमें एडिशन यह है कि वे भी कर सकते हैं।

श्री प्रकाश चन्द्र सेठी : यहीं से नाम भेजना शुरू करेंगे।

श्री घटम विहारी बाजपेयी : अगर, यहीं से नाम भेजना शुरू करेंगे तो पहले सेठी जी का नाम जायेगा।

DR. VASANT KUMAR PANDIT : Through you, Sir, I wish to ask the Hon. Minister of Home Affairs whether he has been constantly acquainted and informed that the Tribunals, the existing ones and the new ones that have been set up, are grossly understaffed; they have no stationery, many of the Tribunals have no accommodation and, therefore, the working is not efficient and they suffer grossly in doing their work. In this connection may I ask the Hon. Minister what provisions has been made in the budget for setting up these Tribunals by the Assam Government and what matching grant you are going

to give so that efficient working of the Tribunals will be ensured ?

**SHRI P.C. SETHI :** Whatever may be the position with regard to old Tribunals, as far as the new Tribunals are concerned, the Assam Government will be providing the budgetary support for the expenditure of these Tribunals and all necessary staff, furniture, accommodation and conveyance will be provided to these Tribunals because they would not be having their sitting at one place but would be moving from place to place in order to detect the persons or even if they are constituted in every constituency.

**SHRI INDRAJIT GUPTA :** I would like to know from the Home Minister (a) whether in view of the fact that in the scheme of the new Tribunals which is now under contemplation the operation of the 1950 Act, immigration into Assam, is being now rendered infructuous, it means that the category of bonafide refugees, displaced persons, who were forced to leave their hearth and home due to certain circumstances will continue to be recognised as such or whether that is being eliminated; (b) in the case of those who are to be detected, because they have come after 1971, whether the electoral rolls of 1970 will be taken to at least verify that all those who had been on the voters' list in 1970 are to be regarded as Indian citizens; and (c) how will all these arrangements apply to the Nepalese who have nothing to do with 1971 at all; I believe there was some arrangements between India and Nepal in 1976; so, in the case of Nepalese, the citizens of Nepal, who have entered, whether this deadline, cut-off year, will be the same as for the other people or whether some different arrangement is being made for them.

**SHRI P.C. SETHI :** As far as the details of the working of this law are concerned, the Bill is coming before the House for discussion and we shall discuss all the details at that time. But I would like to say that, as far as the operation of the 1950 Act is concerned,

that has been stayed because 1950 and 1971, we have still kept open for negotiations because it is likely that, if some negotiations start, some reasonable settlement might be arrived at. As far as the other parts of the question are concerned, we would certainly take care of them when the Bill comes up for discussion.

**SHRI INDRAJIT GUPTA :** I had asked one specific question; it is very important; it concerns lakhs of people. If the working of the 1950 Act is stayed, does it mean that the protection which was given under that to genuine refugees, displaced persons, is now being removed, they are not going to get that protection ?

**SHRI P.C. SETHI :** As far as the genuine refugees are concerned, to whom the Government of India through various negotiations and agreements had given protection, that will remain. We have also received a representation in this connection and that is also under consideration; before the Bill is finally passed by this august House, that will be considered.

**SHRI SONTOSH MOHAN DEV :** At the outset I congratulate the Government on this Ordinance and specially the provisions. This statement by Mr. Vajpayee gives the crux of the Assam problem. He has said that there are certain areas in which there are only Bangladeshis. This idea should not be projected in this House. There are no such areas where only Bangladeshis are there. This is how all the Bengali Muslims and Hindus are being treated by certain political parties. This is the problem before Assam. This provision of 3 km and others have been done by the representation of the linguistic and religious minorities for which I congratulate the Government.

Two things I want to know...Sir, please don't stop me. You have allowed them so much, I will put only pointed question.

Firstly, with the promulgation of Immigration Act and with the present set up of Tribunals with three Judges, I want to know whether the previous Tribunals will be in existence or not or whether they will become infructuous.

No. 2 :—Two points have been raised by Mr. Indrajit Gupta. We ourselves have drawn the attention of the Prime Minister and the Home Minister and they are considering it. I will again appeal to them that when this Bill comes, due consideration should be given.

I would like to know. You have given the cut-off date from 1971 and those Tribunals have detected, deleted and deported the people who have come before 1971 because the Tribunals were there upto 1969. So, those people who have been deported—some of them might have come back through West Bengal, Tripura and Assam again and that may be before 1971. So what will be the position of those people according to the present Tribunals. Will the Home Minister be kind enough to explain?

MR. SPEAKER : Once deported; how will they be taken back?

SHRI SONTOSH MOHAN DEV : Because the cut-off year is 1971 but the Tribunal was of 1969.

SHRI P.C. SETHI : It is possible that some of the deported persons might have infiltrated back through clandestine methods. But, as far as they are concerned, they will be certainly taken care of as far as this Act is concerned.

श्री संयुक्त मुखर्जी : जनाब स्पीकर साहब, मैं आपकी मार्केट होम मिनिस्टर से गुजारिश कर रहा हूँ कि यह विदेशी और गैर-विदेशी होने का क्या मयार है? क्या भारतीय जनता पार्टी जिसको कह दे वही विदेशी है, या कोई मयार है अपोजीशन के लोगों का जिसके

मुताबिक कहा जा सकता है कि यह विदेशी है और यह गैर-विदेशी है? क्योंकि हम ही लोगों के लिये कहा जा रहा है।

श्री प्रमल बिहारी वाजपेयी : मुसलमानों को कोई विदेशी नहीं कह रहा है।

प्रमल महोदय : वह तो ट्राइब्यूनल रिसाइट करेगा।...

(Interruptions)

SHRI SONTOSH MOHAN DEV : Can you identify? You said that there are certain areas full of Bangladeshis. Let him identify.

SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE : There are areas. We are prepared to identify. I had a talk with the Governor and the local police.

PROF. K.K. TEWARY : Sir, these are the people who are doing things against Muslims and Hindus.

(Interruptions)

MR. SPEAKER : No cross talk, please. Hon. Members should talk to me and not to the other members directly.

श्री बाबू राव पराजपे : साफ शब्दों में कहा है कि हिन्दू मुसलमानों का कोई मामला नहीं है। यह गलत प्रचार कर रहे हैं। बगला देन वाले बंगलादेशी हैं।...

(व्यवधान)

श्री प्रकाश चन्द्र सेठी : यह सवाल पैदा ही नहीं होता। जहाँ तक असम में आए हुए इन्फिल्ट्रेटर्स का सवाल है उसकी कट आफ डेट 25 मार्च, 1971 दी हुई है। इस लिए हर एक को विदेशी समझना यह मुनासिब नहीं है।

MR. SPEAKER : The Skariah Thomas...not here. Shri Indrajit Gupta.